GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 30 Nov , 2024

Edition: International

Table of Contents

Page 02 **Syllabus : GS 1 & 3 : भूगोल और आपदा प्रबंधन**	चक्रवात फेंगल आज दोपहर पुडुचेरी तट को पार करेगा
Page 05 **Syllabus : GS 3 : अर्थव्यवस्था**	वैज्ञानिकों, उद्योग जगत ने नए बीज विधेयक पारित करने और नीति में बदलाव की मांग की
Page 12 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	युगांडा में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 20 हुई, कई लोग लापता
Page 13 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	नोट्रे डेम ने आग लगने के पांच साल बाद अपने नए इंटीरियर का अनावरण किया
In News	नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय-स्वास्थ्य**	भारतीयों को गर्भनिरोधक जिम्मेदारी साझा करने की जरूरत है

It's about quality

Page 02 : GS 1 & 3 : Geography and Disaster Management

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना दबाव क्षेत्र एक गहरे दबाव क्षेत्र में तब्दील हो गया है और इसके आगे बढ़कर चक्रवात फेंगल में तब्दील होने की संभावना है।

- यह सिस्टम वर्तमान में उच्च समुद्री सतह तापमान (एसएसटी) वाले क्षेत्र के करीब है, जिससे इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

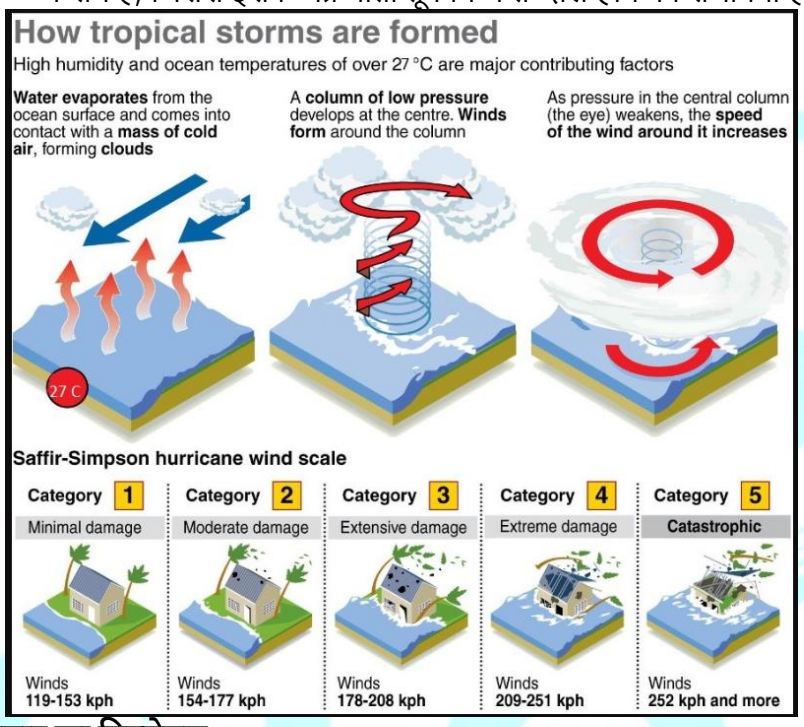

Sharp showers: Rain lashed Chennai under the influence of the cyclone that may make landfall on Saturday. B. VELANKANNI RAJ

Cyclone Fengal to cross Puducherry coast today noon

The Hindu Bureau
CHENNAI

With the slow-moving weather system gathering pace, the Regional Meteorological Centre (RMC), Chennai, announced that Cyclone Fengal will cross the coast close to Puducherry by Saturday afternoon.

The RMC has maintained the red alert – indicating isolated extremely heavy rainfall – in seven coastal districts for Saturday. Intense rain will lash other districts.

On the day of the cyclone's landfall, Chennai and its neighbouring districts, Cuddalore, Puducherry, Villupuram, and Kallakurichi will receive intense rain. With the weather system consolidating itself, it is likely to bring heavy rain in north Tamil Nadu till Saturday, and in the Western Ghat districts and interior parts from December 1 to December 3.

Orange and yellow alerts have been issued for other districts which are expected to receive heavy to very heavy rain. The Cauvery delta districts and north interior districts, too, may receive heavy to very heavy rain on Saturday.

The RMC has said Cyclone Fengal will cross the north Tamil Nadu-Puducherry coast between Karaikal and Mamallapuram as a cyclonic storm by Saturday afternoon. It would have a wind speed of 70-80 kmph gusting to 90 kmph.

समाचार का विश्लेषण:

- **'फेंगल' नाम की उत्पत्ति**
- 'फेंगल' नाम सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसकी जड़ें अरबी भाषा में हैं।
  - o यह भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के संयोजन को दर्शाता है।

- **चक्रवात नामकरण प्रक्रिया:**
  - o उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) पैनल द्वारा रखा जाता है।
  - o इस पैनल में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे 13 सदस्य देश शामिल हैं।
  - o प्रत्येक सदस्य देश संभावित चक्रवातों के नामों की एक सूची प्रस्तुत करता है, और इन नामों का उपयोग क्षेत्र में चक्रवातों के बनने के क्रम में क्रमिक रूप से किया जाता है।

o 2004 से लागू यह प्रणाली जनता तक तूफानों की आसान पहचान और प्रभावी संचार सुनिश्चित करती है।

UPSC Mains Practice Question:

प्रश्न: उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से आप क्या समझते हैं? विस्तार से बताइए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। (250 Words /15 marks)

GEO IAS
It's about quality

Page 05: GS 3 : Economy - Agriculture

राष्ट्रीय बीज कांग्रेस (एनएससी) के दूसरे दिन विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार से 2004 के बीज विधेयक और 2002 की बीज नीति को आधुनिक बनाने का आग्रह किया।

- उन्होंने बीज क्षेत्र में मौजूदा प्रगति के साथ नीतियों को संरेखित करने और किसानों की चिंताओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Scientists, industry demand passage of new Seeds Bill, changes in policy

A. M. Jigeesh
VARANASI

On the second day of the three-day National Seed Congress (NSC), scientists, experts, and industry partners asked the Centre to revisit and modernise the Seeds Bill of 2004 and the Seeds Policy of 2002 to incorporate the latest developments in the sector. At a panel discussion as part of the 13th NSC, the experts also demanded strategic interventions to face the challenges faced by the seed sector.

The Seeds Bill, introduced in Parliament in 2004, was not passed due to opposition from farmers. Experts argued that the policies must be in tune with the contemporary situation in the seeds sector and the concerns of farmers should be incorporated in the new policies.

Experts say that seed certification standards in India are much lower than international standards. PTI

"A balanced focus on innovation, farmer empowerment, and policy reforms can pave the way for a resilient and globally competitive seed industry," said Shiv Kumar Agarwal, regional coordinator of International Center for Agricultural Research in the Dry Areas.

Dr. Agarwal told *The Hindu* that the Seeds Bill needs to be reworked. "The present Bill is 20 years old. Many things have changed. But it can still be sent to all stakeholders so that issues raised by farmers can be addressed. It is about working together. The public sector – the government – is good in science and the private sector is very good in taking science to the farmers. So they must join together to deliver the best products to the farmers who need them so that they can use quality seeds efficiently and affordably," Dr. Agarwal said.

Malvika Dadlani, former Joint Director of Indian Agriculture Research Institute, said the country's seed quality assurance system was weak and should be strengthened on issues such as adhering to international standards.

"Seeds Act, 1966 and Seeds Rules, 1968 have not been revised. Our seed certification standards are much lower than international standards," she said, adding that the proposed Seeds Bill was pending for too long and the existing National Seeds Policy had also not been revised. "We have to clearly define what is a farmer seed and what is a commercial seed. Defining them is very important," she said.

2004 के बीज विधेयक की चुनौतियाँ

- 2004 में पेश किया गया बीज विधेयक किसानों के विरोध के कारण पारित नहीं हो सका।

- विशेषज्ञों ने पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में हुए बदलावों को संबोधित करने के लिए विधेयक को संशोधित करने के महत्व पर बल दिया।
- किसानों को कुशलतापूर्वक और किफ़ायती तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण बताया गया।

कमज़ोर बीज गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली

- बीज अधिनियम 1966 और बीज नियम 1968 के तहत स्थापित मौजूदा बीज गुणवत्ता आश्वासन तंत्र पुराने हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफल हैं।
- विशेषज्ञों ने वैश्विक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को मज़बूत करने का आह्वान किया।

स्पष्ट परिभाषाओं की आवश्यकता

- "किसान बीज" और "वाणिज्यिक बीज" को परिभाषित करने में स्पष्टता की कमी है, जिसे किसी भी संशोधित नीति या कानून में संबोधित करने की आवश्यकता है।

रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता

- विशेषज्ञों ने एक लचीला और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बीज उद्योग बनाने के लिए नवाचार, किसान सशक्तिकरण और नीति सुधारों पर संतुलित ध्यान देने की वकालत की।

निष्कर्ष

- क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए बीज विधेयक और नीति का आधुनिकीकरण अनिवार्य है।
- हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गुणवत्ता वाले बीज सुलभ और सस्ते हों।

बीज की गुणवत्ता और भारतीय कृषि

- **महत्व**
  - o उच्च उपज: गुणवत्ता वाले बीज किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादकता और लाभप्रदता सुनिश्चित करते हैं।
  - o लचीलापन: कीटों, बीमारियों और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाते हैं।
  - o स्थिरता: रासायनिक इनपुट की आवश्यकता को कम करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देते हैं।
  - o खाद्य सुरक्षा: बढ़ती आबादी की खाद्य मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **चुनौतियाँ**
  - o पुरानी नीतियाँ: बीज अधिनियम (1966) जैसे मौजूदा कानून आधुनिक कृषि आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
  - o निम्न गुणवत्ता आश्वासन: बीज प्रमाणन मानक अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से नीचे हैं।
  - o उच्च लागत: कई छोटे और सीमांत किसानों के लिए गुणवत्ता वाले बीज अप्राप्य हैं।
  - o जागरूकता की कमी: किसानों को अक्सर प्रमाणित बीजों के लाभों के बारे में जानकारी की कमी होती है।

- आगे की राह
  - o नीति सुधार: तकनीकी प्रगति को प्रतिबिंबित करने और किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए बीज कानूनों का आधुनिकीकरण करें।
  - o बुनियादी ढांचे का विकास: बीज परीक्षण और प्रमाणीकरण सुविधाओं को मजबूत करना।

o सार्वजनिक-निजी सहयोग: बीज की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना।
o किसानों को शिक्षित करना: किसान जागरूकता और विस्तार सेवाओं को बढ़ाना।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: गुणवत्ता आश्वासन, नवाचार और किसान सशक्तिकरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत की बीज नीतियों और 2004 के बीज विधेयक पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर चर्चा करें। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए बीज उद्योग को मजबूत करने के उपाय सुझाएँ। (150 Words /10 marks)

GEO IAS
It's about quality

पूर्वी युगांडा के बुलाम्बुली जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 20 लोगों की मौत हो गई और 750 लोग विस्थापित हो गए।

Uganda landslides: toll hits 20, many persons missing

Associated Press
KAMPALA

More bodies buried under the mud were retrieved in eastern Uganda on Friday and an injured person died in a hospital, bringing the death toll from this week's landslides to 20, officials said as search efforts pressed on in the stricken area.

Heavy rains had triggered the landslides that engulfed six villages in the mountainous district of Bulambuli, 280 km east of Kampala, Uganda's capital, on Wednesday night. Some 125 houses were destroyed.

The Uganda Red Cross Society spokesperson Irene Kasiita told pressperson that bodies of four more people were found on Friday while a fifth person, one of the injured in the landslides, died at Mbale Hospital. The society in a statement said 750 people had been displaced, with 216 of those living temporarily at a neighbouring school while others were being housed by relatives.

The Bulambuli Resident District Commissioner Faheera Mpalanyi said soldiers have been deployed to help with the digging.

"More bodies are still buried under the heaps of soils and stones and we are trying as much as we can to recover them," she said.

Local officials told a journalist that an excavator would be brought to assist in the rescue efforts, but the roads were covered in mud and rain was still falling. The impacted area is about 50 acres with homesteads and farmlands spread downhill.

Volunteers search for bodies after a landslide buried dozens of homes in Bulambuli district, Uganda on Friday. REUTERS

- बचाव अभियान जारी है, बचाव प्रयासों में सहायता के लिए सैनिकों को तैनात किया गया है।

बुलमबुली, युगांडा - समाचार में स्थान

- स्थान: युगांडा की राजधानी कंपाला से 280 किमी पूर्व में, पहाड़ी क्षेत्र में बुलमबुली जिला।
- घटना: बुधवार रात भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से छह गाँव प्रभावित हुए।
- प्रभाव:
- मृत्यु दर: 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, शव अभी भी बरामद किए जा रहे हैं।
- विस्थापन: 750 लोग विस्थापित हुए, जिनमें से 216 को अस्थायी रूप से पास के एक स्कूल में शरण दी गई।

Page 13 : Prelims Fact

पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल, फ्रांसीसी गोथिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति, को 2019 की विनाशकारी आग के बाद आंशिक रूप से बहाल किया गया है।

- पुनर्निर्मित अंदरूनी भाग, जिसमें गुंबददार छत और साफ किए गए पत्थर के काम शामिल हैं, का अनावरण फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के समक्ष किया गया।
- 8 दिसंबर, 2024 से आम लोग इस प्रतिष्ठित स्थल पर फिर से जा सकते हैं।

नोट्रे डेम कैथेड्रल:

- स्थान: सीन नदी के तट पर पेरिस, फ्रांस में स्थित है।
- निर्माण: निर्माण 1163 में शुरू हुआ, 1345 में पूरा हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक चला।
- वास्तुशिल्प शैली: फ्रेंच गोथिक, जिसमें फ्लाइंग बट्रेस, रिब्ड वाल्ट और नुकीले मेहराब जैसी विशेषताएं हैं।

प्रसिद्ध विशेषताएं:

- गुलाब की खिड़कियाँ: तीन बड़ी, प्रतिष्ठित रंगीन कांच की खिड़कियाँ।
- मूर्तियाँ: बाइबिल के पात्रों और दृश्यों की विस्तृत नक्काशी।
- शिखर: मूल रूप से 13वीं शताब्दी में निर्मित, 2019 की आग के दौरान ढह गया।
- ऐतिहासिक महत्व: शाही शादियों, नेपोलियन बोनापार्ट के राज्याभिषेक और जोन ऑफ आर्क के संत घोषित होने जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी की।
- 2019 की आग: विनाशकारी आग ने छत और शिखर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इसे बहाल करने के लिए वैश्विक प्रयास शुरू हो गए।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: अपने स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए पहचाना जाता है।
- पर्यटन स्थल: सालाना लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है।

The altar of Notre Dame cathedral in Paris, seen on Friday, more than five years after a fire ravaged the landmark. AFP

Notre Dame unveils its renewed interior five years after fire

Associated Press
PARIS

After more than five years of frenetic, but sometimes interrupted, reconstruction work, Notre Dame Cathedral showed itself anew to the world on Friday, with rebuilt soaring ceilings and creamy good-as-new stonework erasing somber memories of its devastating fire in 2019.

Images broadcast live of a site visit by French President Emmanuel Macron showed the inside of the iconic cathedral as worshippers might have experienced it in previous centuries, its wide, open spaces filled with bright light on a crisp and sunny winter's day that lit up the vibrant colors of the stained glass windows.

Outside, the monument is still a construction site, with scaffolding and cranes. But the renovated interior – shown in its full glory on Friday for the first time before the public is allowed back in on December 8 – proved to be breathtaking.

Gone are the gaping holes that the blaze tore into the vaulted ceilings, leaving charred piles of debris. New stonework has been carefully pieced together to repair and fill the wounds that had left the cathedral's insides exposed to the elements. Delicate golden angels look on from the centerpiece of one of the rebuilt ceilings, seeming to fly again above the transept.

The cathedral's bright, cream-coloured limestone walls look brand new, cleaned not only of dust from the fire but also of grime that had accumulated for centuries.

The cathedral attracted millions of worshippers and visitors annually before the fire forced its closure and turned the monument into a no-go zone except to artisans, architects and others mobilised for the reconstruction.

In News : Network Readiness Index 2024

2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (एनआरआई) में भारत की बढ़त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और गवर्नेंस में देश की प्रगति को दर्शाती है।

- डिजिटल इंडिया और भारतनेट जैसी पहलों से प्रेरित होकर, देश डिजिटल परिवर्तन, खासकर एआई और दूरसंचार में अग्रणी बन रहा है।

NRI 2024 में भारत की बेहतर नेटवर्क तत्परता

- भारत ने नेटवर्क तत्परता सूचकांक (एनआरआई) 2024 में अपनी रैंक में उल्लेखनीय सुधार किया है, जो 2023 में 60वें स्थान से बढ़कर 49वें स्थान पर पहुंच गया है।
- देश का स्कोर 49.93 से बढ़कर 53.63 हो गया, जो प्रौद्योगिकी, शासन और बुनियादी ढांचे में प्रगति को दर्शाता है।
- भारत ने एआई वैज्ञानिक प्रकाशन, एआई प्रतिभा एकाग्रता और आईसीटी सेवा निर्यात के लिए विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया।
- देश फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) सदस्यता, मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफ़िक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ के लिए दूसरे स्थान पर रहा।
- भारत घरेलू बाजार पैमाने के लिए तीसरे और दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश के लिए चौथे स्थान पर रहा।
- निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, भारत ने अपने आय समूह के भीतर डिजिटल प्रगति में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) अवलोकन

- NRI 133 अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नेटवर्क रेडीनेस के आधार पर रैंक करता है, जिसमें चार प्रमुख स्तंभों का मूल्यांकन किया जाता है: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव।

- यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने की देश की क्षमता का मूल्यांकन करता है।
- NRI रैंकिंग निर्धारित करने के लिए 54 चर का उपयोग करता है, जो बुनियादी ढांचे, डिजिटल अपनाने, नीतियों और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह सूचकांक INSEAD और विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- NRI डिजिटल परिवर्तन में वैश्विक नेताओं पर प्रकाश डालता है, यह जानकारी प्रदान करता है कि देश विकास को गति देने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं।
- यह डिजिटल बुनियादी ढांचे में नीतिगत निर्णयों और निवेशों को निर्देशित करने में मदद करता है।

डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल

- **सरकारी पहल**

  o डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: 2015 में शुरू किया गया, इसने ब्रॉडबैंड एक्सेस, डिजिटल साक्षरता और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन बढ़ाया है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

  o भारतनेट पहल: इसका उद्देश्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को कम करना और ई-गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ाना है।

  o 5G और भविष्य की दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ: 2022 में भारत के 5G रोलआउट ने मोबाइल ब्रॉडबैंड की गति को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिससे इसकी वैश्विक रैंकिंग 118वें से सुधरकर 15वें स्थान पर आ गई है। सरकार की 5G इंटेलिजेंट विलेज पहल और भारत 6G विजन का उद्देश्य ग्रामीण नवाचार के लिए 5G का लाभ उठाना और भारत को 6G तकनीक में अग्रणी बनाना है।

डिजिटल विकास का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय नीतियाँ और योजनाएँ

- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP) 2018: दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: 2021 में लॉन्च किया गया, यह निर्बाध राष्ट्रव्यापी परिवहन और रसद को बढ़ाने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढाँचे के विकास को एकीकृत करता है।
- राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) रणनीति: AI को आर्थिक विकास के चालक के रूप में बढ़ावा देती है, जिसमें AI प्रतिभा और वैज्ञानिक प्रकाशनों के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान दिया गया है। AI को स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए भी लक्षित किया गया है।
  - कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम कौशल भारत और पीएमजीदिशा जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल और तकनीकी कौशल से लैस करना है, जिससे वैश्विक कार्यबल में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।

- इन पहलों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे लोगों को डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में मदद मिली है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की बेहतर रैंकिंग में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें। सरकारी पहल देश के डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक तकनीकी स्थिति को कैसे बढ़ाती है? (250 Words /15 marks)

GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 06 Editorial Analysis

Indians need to share contraceptive responsibility

Samira Rizvi
a public health student at the Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai

Thanooja N.
a public health student at the Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai

M. Sivakami
a professor at the Tata Institute of Social Sciences (TISS)

In 1952, India pioneered a national programme for family planning, whose focus has since changed – from improving maternal and child health to stabilising the population. As this programme evolved, so too did permanent methods of contraception.

During 1966-70, about 80.5% of all sterilisation procedures in India were vasectomies. This percentage declined every year due to changing policies that, together with other factors, placed less and less of an emphasis on vasectomies. The five rounds of the National Family Health Survey (NHFS) also show the use of male sterilisation, especially in the last three decades, to be steadily decreasing in all States. In fact, the vasectomies percentage remained constant at around 0.3% in NFHS-4 (2015-16) and NFHS-5.

Gender and the disparity

This trend goes against Section 4.8 of the National Health Policy 2017, which aimed to increase the fraction of male sterilisations to at least 30%. Even today, India is far from meeting this target. Official data also show a large disparity between the rates of female and male sterilisation – 37.9% and 0.3%, respectively. Such huge differences indicate that women continue to bear virtually all of the burden of sterilisation, which in turn poses a challenge for India to achieve Sustainable Development Goal 5 – 'gender equality and empowerment of all women and girls by 2030' – among others.

In one attempt to bridge this gap, the world observes Vasectomy Day on the third Friday of November (it was on November 15 this year). In 2017, India observed a 'vasectomy fortnight' as well.

The initiative is to revitalise the procedure by increasing awareness, generating demand among men, and debunking misconceptions. In the end, the goal is for people already looking for contraceptives as well as those who would if they knew about safe options to consider vasectomies more favourably.

But for these concerted efforts, policies still overlook multiple issues on the ground, keeping them ineffective and allowing the gap between male and female sterilisation rates to persist.

With more awareness of gender equality and rights, it is possible to build a society in which male sterilisation is accepted as normative

The ground reality, solutions

For example, two of the three writers of this article surveyed a village in Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra, in March 2024 as part of a field exercise. The women said sterilisation was their responsibility and that the men do not believe they need to have vasectomies. Most of them also expressed a belief that men should not be "burdened" by it because they already work hard to make ends meet, and that undergoing the procedure could rob the men of their day's wages, worsening their hardship.

These women were also unaware of the Indian government's cash incentives to those who undergo vasectomies to offset the loss of wages. In fact, many studies in India have suggested that illiteracy, male egos, misconceptions about its impact on libido, and family opposition have led to the poor acceptance of vasectomies. Many men are not aware of their role in ensuring the safe passage of reproductive years in the lives of their female partners.

The unavailability of skilled providers has aggravated the situation, especially in rural areas. To make matters worse, many trained community health workers themselves know little about no-scalpel vasectomies.

As things stand, with increasing awareness of gender equality and rights, it is certainly possible to build a society in which male sterilisation is accepted as normative through proper and timely course correction.

As a first step, sensitisation should begin during early adolescence in schools, where awareness programmes and monitored peer-group discussions can lay the foundation for accepting sterilisation as a shared responsibility. Sustained social and behaviour change communication initiatives will be instrumental in debunking myths around and destigmatising vasectomies. Vasectomy is a safe and simple procedure compared to tubectomy, the corresponding surgical procedure for women involving their fallopian tubes.

Second, these information, education and communication activities should be supplemented with greater conditional cash incentives for vasectomies with the goal to improve male participation.

A study in Maharashtra in 2019 showed that more men in rural tribal areas opted for vasectomies after being offered a conditional cash incentive. Madhya Pradesh's move in 2022 to increase this incentive by 50% is appreciable in this light.

An international comparison

Third, India should draw from the lessons from other countries that have increased vasectomy uptake. South Korea has the highest prevalence of the procedure worldwide, and has reported that men are more likely to shoulder contraceptive responsibilities as a result of progressive societal norms and greater gender equality. Similarly, Bhutan has popularised vasectomy among its men by making the procedure socially acceptable, availing good-quality services, and organising government-run vasectomy camps. Brazil increased vasectomy uptake by running awareness campaigns on mass media. The prevalence rate has risen, from 0.8% in the 1980s to 5% in the last decade.

Greater public awareness of vasectomies allows both partners in a union to make informed family planning decisions. In tandem, the government must strengthen the national health system to align with policy objectives, invest in training more health professionals to perform the procedure, and promote technical advancements to increase the use of non-scalpel vasectomies.

The resulting policy should not have only intention. It should also lay out concrete steps to achieve its targets. The need of the hour is demand- and service-focused efforts rather than mere formulation.

GS Paper 02 : सामाजिक न्याय- स्वास्थ्य

PYQ: (UPSC CSE (M) GS-1 2021): जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करें तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों को विस्तार से बताएं। (250 words/15m)

UPSC Mains Practice Question: सुरक्षित और सरल विकल्प होने के बावजूद, भारत में पुरुष नसबंदी का बहुत कम उपयोग किया जाता है। पुरुष नसबंदी अपनाने में सामाजिक-सांस्कृतिक और प्रणालीगत बाधाओं की जांच करें और परिवार नियोजन में इस लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ। (250 Words /15 marks)

संदर्भ:

- भारत में परिवार नियोजन पहलों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1952 में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने और जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम से हुई थी।
- पिछले कुछ वर्षों में, कार्यक्रम विकसित हुआ है, लेकिन एक चौंकाने वाली प्रवृत्ति उभरी है: स्थायी गर्भनिरोधक विधियों को अपनाने में लिंग असमानता।
- यह असमानता लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए प्रणालीगत चुनौतियों को रेखांकित करती है, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 5 के संदर्भ में: 2030 तक सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।

पुरुष नसबंदी में गिरावट

- 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, भारत में नसबंदी का प्रमुख तरीका पुरुष नसबंदी था, जो ऐसी प्रक्रियाओं का 80% से अधिक हिस्सा था।
- हालांकि, नीतिगत बदलावों, गलत धारणाओं और सामाजिक दृष्टिकोणों के कारण इसमें भारी गिरावट आई है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के पांच दौरों में पुरुष नसबंदी दरों में लगातार गिरावट देखी गई है, जबकि सबसे हालिया सर्वेक्षणों, NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 में कोई प्रगति नहीं देखी गई है।
- यह 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विपरीत है, जिसमें पुरुष नसबंदी दरों को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।

भारत में पुरुष और महिला नसबंदी दरों के बीच असमानता के पीछे कारण

- **सामाजिक अपेक्षाएँ और जिम्मेदारी**
  - o कई भारतीय समुदायों में, परिवार नियोजन को मुख्य रूप से एक महिला की जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है।
  - o यह धारणा सांस्कृतिक अपेक्षाओं द्वारा कायम रखी जाती है कि महिलाएँ प्राथमिक देखभालकर्ता हैं और इसलिए उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य का प्रबंधन करना चाहिए।
  - o दूसरी ओर, पुरुषों को अक्सर कमाने वाले के रूप में उनकी भूमिका के कारण इन जिम्मेदारियों से मुक्त माना जाता है।
  - o ये जड़ जमाए हुए दृष्टिकोण इस विचार को बनाए रखते हैं कि महिलाओं को नसबंदी की शारीरिक और भावनात्मक लागतों को सहना चाहिए, जबकि पुरुष इसमें शामिल नहीं होते हैं।

- **पुरुष नसबंदी के बारे में मिथक और गलत धारणाएँ**
  - o पुरुष नसबंदी के बारे में गलत धारणाएँ इसके कम प्रचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - o कई पुरुषों को डर है कि यह प्रक्रिया उनके पुरुषत्व, कामेच्छा या शारीरिक शक्ति को प्रभावित करेगी, जबकि चिकित्सा साक्ष्य इसके विपरीत हैं।
  - o यह डर विश्वसनीय जानकारी की कमी और व्यापक मिथकों, जैसे कि पुरुष नसबंदी से नपुंसकता या नपुंसकता का एक रूप हो सकता है, के कारण और भी बढ़ जाता है।
  - o ऐसी निराधार मान्यताएँ पुरुषों को इस प्रक्रिया पर विचार करने से हतोत्साहित करती हैं, भले ही यह महिला नसबंदी का एक सुरक्षित और कम आक्रामक विकल्प हो।

- **आर्थिक और व्यावहारिक बाधाएँ**
  - o आर्थिक कारणों से पुरुष पुरुष नसबंदी करवाने से और भी हतोत्साहित होते हैं।

- कई परिवार पुरुषों की आय पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, और दैनिक मजदूरी पर रहने वालों के लिए एक दिन के लिए भी काम से दूर रहने की संभावना असहनीय लग सकती है।
- खोई हुई मजदूरी की भरपाई के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी नकद प्रोत्साहनों के बावजूद, इन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता कम है।
- महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 2024 के एक क्षेत्र अध्ययन में साक्षात्कार की गई महिलाओं ने चिंता व्यक्त की कि पुरुष नसबंदी उनके परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगी।
- यह सरकारी सहायता प्रणालियों के बारे में संचार में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।

पितृसत्तात्मक प्रतिरोध और महिला अनिच्छा

- दिलचस्प बात यह है कि पुरुष नसबंदी का प्रतिरोध केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि कई महिलाएँ भी पुरुष नसबंदी को अपने पतियों के लिए अनुचित या अनावश्यक मानती हैं।
- पितृसत्तात्मक घरों में, महिलाएँ सामाजिक मानदंडों को आत्मसात कर सकती हैं जो केवल उन्हें प्रजनन संबंधी ज़िम्मेदारियाँ सौंपती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षात्कार की गई कुछ महिलाओं का मानना था कि अपने पतियों से पुरुष नसबंदी करवाने के लिए कहना अपमानजनक होगा या वैवाहिक कलह का कारण बन सकता है।
- यह लैंगिक असंतुलन को और बढ़ाता है और परिवार नियोजन में महिलाओं के बोझ के चक्र को बनाए रखता है।

कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और जागरूकता की कमी

- ग्रामीण क्षेत्रों में, कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक सीमित पहुँच समस्या को और बढ़ा देती है।
- यहाँ तक कि जब पुरुष पुरुष नसबंदी करवाने के लिए तैयार होते हैं, तो प्रशिक्षित पेशेवरों की अनुपलब्धता एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाती है।
- इसके अतिरिक्त, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा जानकारी का प्राथमिक स्रोत होते हैं, वे स्वयं पुरुष नसबंदी के विकल्पों, विशेष रूप से नो-स्केलपेल पुरुष नसबंदी जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं।
- जागरूकता की कमी पुरुष नसबंदी को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में कम करती है, जिससे महिला नसबंदी पर निर्भरता बनी रहती है।

लैंगिक समानता के लिए निहितार्थ

- यह लैंगिक असमानता लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के व्यापक प्रयासों को कमजोर करती है।
- जब महिलाएं नसबंदी का खामियाजा भुगतती हैं, तो उन्हें अपने दैनिक जीवन और आजीविका में अधिक स्वास्थ्य जोखिम और संभावित व्यवधानों का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा, सामाजिक कथा जो केवल महिलाओं पर बोझ डालती है, हानिकारक लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करती है और वैवाहिक और पारिवारिक गतिशीलता में साझा जिम्मेदारियों की संभावना को सीमित करती है।
- इन असमानताओं को संबोधित करने के लिए न केवल नसबंदी प्रक्रियाओं की सुरक्षा और सरलता के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि प्रजनन जिम्मेदारियों को देखने के तरीके में सामाजिक बदलाव की भी आवश्यकता है।
- जब तक पुरुषों को परिवार नियोजन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तब तक भारत में लैंगिक समानता हासिल करना एक मायावी लक्ष्य बना रहेगा।

पुरुष नसबंदी अपनाने को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ

- प्रारंभिक शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन पहल
- साझा परिवार नियोजन जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशीलता स्कूलों में शुरू होनी चाहिए।
- सहकर्मी समूह चर्चाओं और संरचित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता और प्रजनन स्वास्थ्य की अवधारणाओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी मौजूदा रूढ़ियों को चुनौती दे सकती है और पुरुष नसबंदी को कलंकमुक्त कर सकती है।
- पुरुष नसबंदी से जुड़ी मिथकों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
- अभियानों को महिलाओं के लिए इसी शल्य चिकित्सा पद्धति ट्यूबेक्टोमी की तुलना में प्रक्रिया की सुरक्षा और सरलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

बढ़े हुए प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं से सीखना

- सशर्त नकद प्रोत्साहन पुरुष भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में 2019 के एक अध्ययन से पता चला है कि वित्तीय प्रोत्साहनों ने ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में अधिक पुरुषों को पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया।
- मध्य प्रदेश का 2022 में इन प्रोत्साहनों को 50% बढ़ाने का निर्णय एक आशाजनक नीति दिशा को दर्शाता है।
- दक्षिण कोरिया, भूटान और ब्राजील जैसे देश मूल्यवान सबक देते हैं।
- दक्षिण कोरिया में पुरुष नसबंदी का उच्च प्रचलन प्रगतिशील लिंग मानदंडों से जुड़ा हुआ है, जबकि भूटान के सरकारी शिविरों और ब्राजील के जन मीडिया अभियानों ने पुरुष नसबंदी दरों को प्रभावी रूप से बढ़ाया है।
- ये उदाहरण दिखाते हैं कि पुरुष नसबंदी को सामान्य बनाना और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करना स्वीकृति को बढ़ा सकता है।

स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना

- भारत सरकार को पुरुष नसबंदी करने के लिए अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करके और गैर-स्केलपेल तकनीकों जैसी तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देकर अपने स्वास्थ्य ढांचे को नीतिगत लक्ष्यों के साथ संरेखित करना चाहिए।
- जागरूकता और पहुँच में निवेश एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है जहाँ पुरुष नसबंदी एक व्यवहार्य विकल्प हो।

निष्कर्ष

- नसबंदी के लिए महिलाओं पर असंगत निर्भरता भारत के परिवार नियोजन प्रयासों में गहरी लैंगिक असमानताओं को उजागर करती है।
- इस अंतर को पाटने के लिए नीतिगत इरादों से कहीं अधिक की आवश्यकता है; इसके लिए शिक्षा, प्रोत्साहन और प्रणालीगत सुधार को एकीकृत करने वाले कार्रवाई योग्य कदमों की आवश्यकता है।
- पुरुष नसबंदी को सामान्य बनाकर और सामाजिक गलतफहमियों को दूर करके, भारत परिवार नियोजन में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे लैंगिक समानता और बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य परिणामों का मार्ग प्रशस्त होगा।